DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS नई दिल्ली, ४ नवंबर, 2022 दैनिक जागरण DAT

DATED

चूक का फायदा उठाने की डीडीए को नहीं दी जा सकती अनुमति

विनीत त्रिपाटी, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को एक सैन्य अधिकारी को भूखंड का आवंटन बहाल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि नवंबर 2019 में पारित अंतरिम आदेश के संबंध में याचिकाकर्ता को सूचित नहीं करने में अपनी चूक का फायदा उठाने की डीडीए को अनुमति नहीं दी जा सकती है। कर्नल एके अरोड़ा ने पूरी राशि का भुगतान किया, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा संपत्ति पर यथास्थिति के आदेश को संप्रेषित करने में डीडीए की विफलता के कारण उन्हें कभी कब्जा नहीं मिला।

अदालत ने कहा कि यह डीडीए के लिए पूरी तरह से अनुचित और मनमाना है कि खरींदार के पक्ष में कब्जा पत्र जारी करने की स्थिति में न होने के बाजवूद वह खरीदार पर 100 प्रतिशत भुगतान करने का दबाव बनाए। डींडीए ने रोहिणी में एक आवासीय भूखंड के आवंटन के लिए अप्रैल 2019 में नीलामी की थी। याचिकाकर्ता कर्नल की दो करोड़ से अधिक की बोली को डीडीए ने स्वीकार कर लिया और इस संबंध में पत्र जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने कुछ भुगतान किया और 90 दिनों के भीतर शेष राशि के भुगतान के लिए मांगपत्र जारी किया गया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सैन्य अधिकारी को भूखंड का आवंटन बहाल करने का दिया निर्देश

था। नवंबर 2019 में हाई कोर्ट ने डीडीए संपत्ति सहित क्षेत्र में भमि के कुछ भूखंडों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। इस आदेश की याचिकाकर्ता को जानकारी नहीं थी तो उन्होंने डीडीए को पत्र भेजकर राशि का भुगतान करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की। डीडीए ने याची को उस आदेश के संबंध में सूचित किए बगैर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उस राशि पर ब्याज देने के साथ समय विस्तार की मंजूरी दे दी। याचिकाकर्ता ने जब मार्च 2020 में अंतिम भुगतान किया तब डीडीए ने अदालत के आदेश के बारे में उन्हें बताया।

इसके बाद डीडीए ने जून 2021 में आदेश पारित करके कहा कि याचिकाकर्ता का उस भूखंड पर अधिकार नहीं हैं, क्योंकि पहले ही उस भूखंड को ई-नीलामी के जरिये वापस ले लिया गया था। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के मद्देनजर डीडीए कब्जा पत्र जारी करने की स्थित में नहीं था। फिर भी इसने याचिकाकर्ता से 75 प्रतिशत भुगतान स्वीकार किया और देरी के लिए ब्याज भी लिया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

Land pooling: deadline extended twice, consortiums yet to be formed

The Hindu Bureau NEW DELHI

None of the three sectors, which are part of the land pooling policy (LPP) and where conditional notices were first issued to landowners, have managed to form consortiums after the expiry of the latest extended deadline (October 30), senior Delhi Development Authority (DDA) officials said on Thursday.

The DDA had issued notices to the landowners, who had expressed interest in the LPP, in three sectors – Sector 10A (Zone N) and Sectors 2 and 3 (Zone P-II) – in May, on condition that they negotiate and convince the remaining

No development work has started in the 104 villages that have been identified for land pooling

landowners to pool their land within a period of 90 days.

The urban body has since extended the deadline twice. However, senior officials say that the negotiations among the landowners "are still under way".

A non-starter

Notified on two occasions
– in 2013 and 2018 – the
LPP has been a non-starter,
with the development
works yet to take off due to

eligibility criteria such as – 70% of the pooled land must be contiguous and the minimum participation rate in an area earmarked for land pooling must be 70%.

The policy aims to provide 17 lakh dwelling units for a population of nearly 80 lakh people. However, the response to it has been lukewarm with only 7,070 applicants, with 7,390 hectares of land (out of the total poolable land of 19,074 hectares), having expressed their interest in the scheme.

No development work has yet started in the 104 villages – which have been divided into six zones and further divided into 129 sectors – that have been identified for land pooling.

While certain amendments to the Delhi Development Act, 1957, have been proposed with the aim of removing the two major roadblocks faced in the LPP's implementation - the criteria of minimum participation rate and contiguity - the urban body had issued conditional notices to start a parallel process to remove the roadthrough blocks negotiations among landowners.

"We will not issue any new conditional notices. We are focusing on the six sectors where notices have been issued already," said a senior DDA official.

millenniumpost

FRIDAY, 4 NOVEMBER, 2022 | NEW DELHI

DDA MAKES PROGESS IN 'JAHAN JHUGGI WAHAN MAKAN' SCHEME

NEW DELHI: Delhi Development Authority in order to address the problems in several slums across Delhi-NCR in their jurisdiction has been working towards projects that will solve the problems of unauthorised colonies in Delhi. Earlier this year, in their budget DDA had announced that they will work on in-situ rehabilitation in six JJ clusters on the PPP model and approximately Rs 2,000 crore had been assigned for the projects. DDA has planned to construct over 10,000 EWS flats for slum dwellers in areas such as Jailarwala Bagh, Rohini, Dilshad Garden, Shalimar Bagh and Haiderpur in the capital. This comes under the 'Jahan Jhuggi Wahan Makan' scheme that aims to ensure that every person has a house and to provide a better and healthy living environment to the residents of these clusters, with modern amenities and facilities. A DDA official stated that the majority of the projects would have made a lot of progress by next year and several families will be able to enjoy the benefits of the flats and scheme. The project will include other public amenities as well such as community parks, dedicated electric sub-stations, sewage treatment plant, dual water pipelines, lifts, underground reservoir for hygienic water supply are available in the flats.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। शुक्रवारं • 4 नवम्बर • 2022

सहारा

प्रधानमंत्री ने गरीबों को सौंपी किस्मत की चाबी : बिधूड़ी

प्रस्तावित योजनाओं

को लेकर केंद्रीय मंत्री

से मिले भाजपा नेता,

जताया आभार

नई दिल्ली (एसएनबी)। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने 3024 गरीबों को मकान की चाबी सौंपे जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह उन गरीबों के किस्मत की चाबी है, जो अब सम्मान के साथ जी सकेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय आवासन मंत्री हरदीप सिंह पूरी से मुलाकात

की और उनका आभार जताया। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, हर्ष मल्होत्रा, सतीश गर्ग भी थे।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना से

गरीब झुग्गीवालों की किस्मत बदल गयी है। यह कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा की सरकार ही कर सकती है। दिल्ली में 10 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट देने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। इन योजनाओं में द्वारका में 25 हजार की क्षमता वाला कर्नवेशन सेंटर, 12 डायवरसिटी पार्क, पांच पलाई ओवर, सड़कें शामिल हैं। इसमें महिपालपुर का अंडरपास और बाईपास भी शामिल है। प्रगति मैदान के पास बनी शानदार टनल, यमुना के किनारों का सौदर्यीकरण और दुनिया का सबसें बड़ा इको पार्क जल्द ही बदरपुर में बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली को प्रदुषण से मुक्ति

दिलाने के लिए केंद्र सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। मौजूदा परियोजनाएं उसका उदाहरण हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की निष्क्रियता की वजह से दिल्ली में तेजी से प्रदूषण बढ़ा

है और अब लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री के साथ दिल्ली में प्रस्तावित अन्य योजनाओं को लेकर भी चर्चा की। बिधूड़ी के मुताबिक मंत्री से उनके समाधान का आश्वासन दिया है। पीएम मोदी ने फ्लैट की ही नहीं किस्मत की भी चाबी दी: भाजपा

पजाब कैसरे

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी दिल्ली की तरफ से धन्यवाद दिया है कि उन्होंने दिल्ली के हजारों झुग्गीवासियों को सम्मान के साथ जीने का हक देते हुए उन्हें फ्लैटों की चाबी दी है। यह सिर्फ फ्लैट की चाबी नहीं, बल्कि उनकी किस्मत की चाबी है।

प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए भाजपा नेताओं का एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्री हरदीप पुरी से मिला। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, महामंत्री हर्ष मलहोत्रा और प्रवक्ता सतीश गर्ग शामिल रहे। भाजपा नेताओं ने दिल्ली में 10 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट देने के लिए भी पुरी का आभार व्यक्त किया। इसमें द्वारका में 25 हजार की



क्षमता वाला कनवेंशन सेंटर, 12 डायवर्सिटी पार्क, पांच फ्लाईओवर और सड़कें जिनमें महिपालपुर अंडरपास और बाईपास भी शामिल हैं।रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार तन्मयता से काम कर रही है और सारी परियोजनाएं

उसका उदाहरण हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की निष्क्रियता के कारण लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है। भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री के साथ दिल्ली की कई और समस्याओं पर भी चर्चा की और मंत्री पुरी ने उन्हें शीघ्र हल करने का अश्वासन भी दिया।

दैनिक भारकर

मोदी जी ने झुग्गीवासियों को फ्लैट्स की ही नहीं, किस्मत की भी चाबी दी: भाजपा

नई दिल्ली भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरी दिल्ली की तरफ से धन्यवाद दिया है कि उन्होंने दिल्ली के हजारों झुग्गीवासियों को सम्मान के साथ जीने का हक देते हए उन्हें फ्लैटों की चाबी दी है। यह सिर्फ फ्लैट की चाबी नहीं उ विल्क उनकी किस्मत की चावी है। प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए भाजपा नेताओं का एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्री हरदीप परी से मिला। प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधुड़ी, महामंत्री हर्ष मलहोत्रा और प्रवक्ता सतीश गर्ग शामिल थे। नेताओं ने हरदीप पूरी से कहा कि दिल्ली के झुग्गी वालों की किस्मत बदल गई हैं और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ही यह कार्य कर सकती है। भाजपा नेताओं ने दिल्ली में 10 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट देने के लिए भी पूरी का आभार व्यक्त किया। इसमें द्वारका में 25 हजार की क्षमता वाला कनवेंशन सेंटर, 12 डायवर्सिटी पार्क, पांच फ्लाई ओवर और सहकें जिनमें महिपालपुर का अंडरपास और बाईपास भी शामिल है, प्रगति



मैदान के पास बनी शानदार टनल, यमुना के किनारों का सौंदर्यीकरण और दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क प्रमुख हैं।

नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार तन्मयता से काम कर रही है और सारी परियोजनाएं उसका उदाहरण हैं लेकिन दिल्ली सरकार की निष्क्रियता के कारण राजधानी के लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है।भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री के साथ दिल्ली की कई और समस्याओं पर भी चर्चा की और मंत्री जी ने उन्हें शीघ्र हल करने का आश्वासन भी दिया।

the pioneer

NEW DELHI I FRIDAY I NOVEMBER 4, 2022

BJP THANKS PM FOR GIVING FLAT KEYS TO POOR

New Delhi: BJP leaders have thanked Prime Minister Narendra Modi on behalf of entire Delhi for giving the keys of flats to thousands of slum dwellers of Delhi giving them the right to live with dignity. It is not just the key to the flat but the key to their fate. A senior delegation of BJP leaders met the Union Minister for Housing and Urban Development, Hardeep Puri, to thank the Prime Minister.*